BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

# भारत की रक्षा शक्ति
# आत्मनिर्भरता से सशक्त राष्ट्रीय सुरक्षा

14 अगस्त, 2026

## भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूती

पिछले एक दशक में भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। यह एक मजबूत, अधिक आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। आत्मनिर्भर भारत द्वारा निर्देशित, निरंतर सुधारों, निवेश और स्वदेशी नवाचार ने रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। देश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों के आधार का भी काफी विस्तार हुआ है। जैसा कि भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, यह परिवर्तन अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और वैश्विक सुरक्षा में योगदान करने की भारत की क्षमता में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

### रक्षा क्षेत्र में निवेश से सैन्य क्षमताओं को मजबूती

- रक्षा बजट में 3.1 गुना वृद्धि: रक्षा बजट 2013-14 में ₹2.53 लाख करोड़ से बढ़कर 2026-27 में ₹7.85 लाख करोड़ हो गया।
- पूंजीगत व्यय में 2.3 गुना वृद्धि: पूंजीगत व्यय भी 2014-15 में ₹94,587.95 करोड़ से बढ़कर 2026-27 में ₹2.19 लाख करोड़ हो गया, जिससे निरंतर आधुनिकीकरण संभव हो गया।

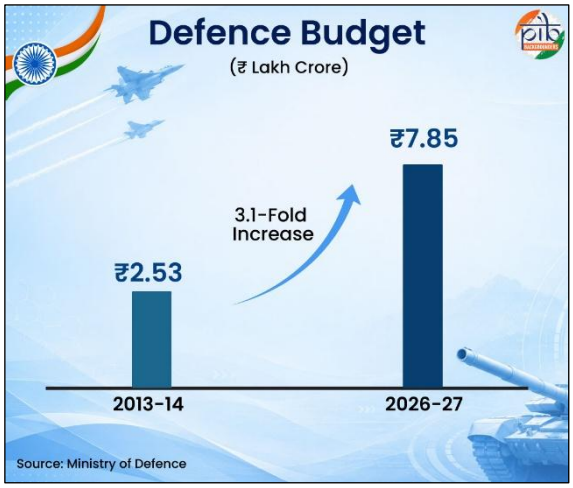

### निवेश से स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा

- 2025-26 में रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
- सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से 76 प्रतिशत उत्पादन और निजी क्षेत्र से 24 प्रतिशत उत्पादन।

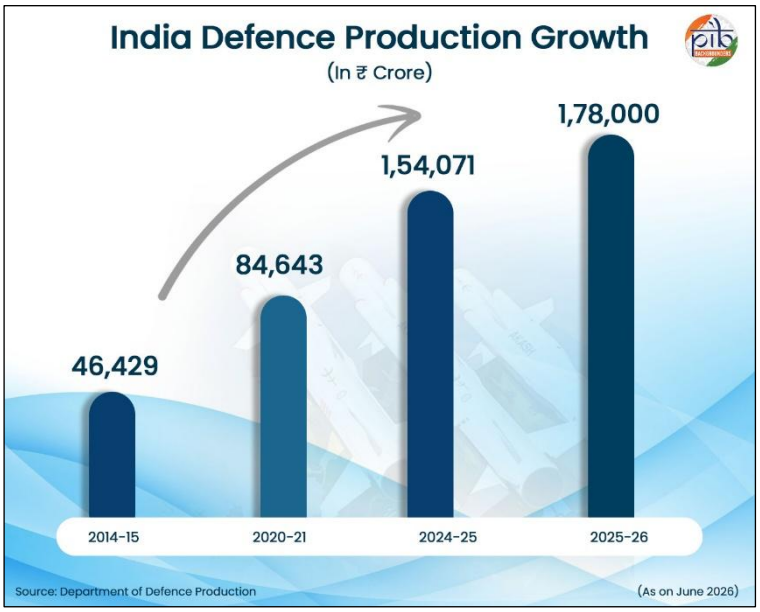


## देश में उद्योग के बल पर निर्यात का वस्तार

- **रक्षा निर्यात में 56 गुना वृद्धि: निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 में ₹686 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में ₹38,424 करोड़ हो गया।**
- निर्यात 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहा है और बारह वर्षों में 5,500 प्रतिशत से अधिक हो गया है।
- वित्त वर्ष 2025-26 में निजी क्षेत्र ने 17,353 करोड़ रुपये या रक्षा निर्यात में 45.16 प्रतिशत का योगदान दिया, जबकि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 21,071 करोड़ रुपये या 54.84 प्रतिशत का योगदान दिया।
- सरकार ने 2029 तक वार्षिक रक्षा उत्पादन में 3 लाख करोड़ रुपये और निर्यात में 50,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है।

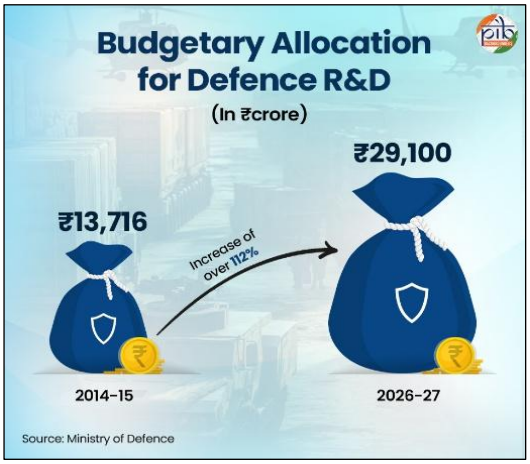


## नवाचार से तकनीकी प्रतिष्ठानों को मजबूती

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास आवंटन 2014-15 में 13,716.14 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 29,100.25 करोड़ रुपये हो गया, जो 112 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।
- 2022-23 से, रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत उद्योग, स्टार्ट-अप और शिक्षा जगत के लिए खोल दिया गया है।
- रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रक्षा परीक्षण पोर्टल (डीटीपी) के माध्यम से 24 डीआरडीओ प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाएं सुलभ हैं। यह पोर्टल घरेलू निर्माताओं, स्टार्टअप्स और उद्योगों को स्वदेशी रक्षा उत्पादन का समर्थन करने के लिए विशेष सरकारी परीक्षण बुनियादी ढांचे तक सशुल्क पहुंच का अनुरोध करने देता है।

## भारत के रक्षा क्षेत्र के उद्योग के आधार को मजबूत करने वाली प्रमुख पहलें

भारत स्वदेशी विनिर्माण, आधुनिक बुनियादी ढांचे और अधिक निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अपनी रक्षा औद्योगिक क्षमता का विस्तार कर रहा है। यह बढ़ता हुआ इकोसिस्टम घरेलू क्षमताओं को मजबूत कर रहा है, नवाचार का समर्थन कर रहा है और एक सशक्त रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण कर रहा है।

### रक्षा अधिग्रहण सुधार

- **भारत की शीर्ष रक्षा खरीद संस्था, रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) स्वदेशी अधिग्रहण के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रही है। इसने डीआरडीओ-डिज़ाइन की गई, भारतीय उद्योग-निर्मित प्रणालियों के ₹6 लाख करोड़ से अधिक के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की है।**
- **प्रमुख स्वदेशी अधिग्रहण लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं: मंजूरी में 62,000 करोड़ रुपये के 97 तेजस एमके-1ए लड़ाकू विमान और 62,700 करोड़ रुपये के 156 एलसीएच प्रचंड हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इन खरीदों से भारत की घरेलू एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार होगा।**
- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020 ने स्वदेशी खरीद और घरेलू विनिर्माण को मजबूत किया। इसने रक्षा डिजाइन, विकास और उत्पादन में भारतीय कंपनियों के लिए अवसरों का भी विस्तार किया।**
- **रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) 2016 ने मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए रक्षा अधिग्रहण को सुव्यवस्थित किया। इसने रक्षा खरीद में बाद के सुधारों की नींव रखी।**
- **रक्षा खरीद नियमावली (डीपीएम) 2025 ने राजस्व खरीद में लगभग ₹1 लाख करोड़ को सुव्यवस्थित किया। इसने तेजी से मंजूरी, स्वदेशी परियोजनाओं के लिए दंड में छूट और दीर्घकालिक आदेशों का आश्वासन दिया।**

**रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2026 का मसौदा**

**डीएपी 2026 में सरल अधिग्रहण श्रेणियों और स्वदेशी डिजाइन और विकास के लिए मजबूत समर्थन का प्रस्ताव है। इसमें 60 प्रतिशत तक की स्वदेशी सामग्री की आवश्यकताओं का भी प्रस्ताव किया गया है।**

### नवाचार को बढ़ावा - आईडीईएक्स, अदिति और टीडीएफ

- ₹498.78 करोड़ के परिव्यय के साथ रक्षा उत्कृष्टता नवाचार (आईडीईएक्स) योजना, 676 स्टार्टअप, एमएसएमई और इनोवेटर्स को शामिल करती है, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2026 तक 551 डिजाइन और विकास अनुबंध संभव होते हैं।
- **अदिति योजना: ₹750 करोड़ के परिव्यय (2023-24 से 2025-26) के साथ स्वीकृत, अदिति नवीन रक्षा प्रौद्योगिकियों में तेजी लाने के लिए रक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।**
- **प्रौद्योगिकी विकास कोष: यह योजना महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी विकास के लिए ₹50 करोड़ तक का अनुदान प्रदान करती है। जून 2026 तक, 334 करोड़ रुपये की 80 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन थीं, जिसमें गहन प्रौद्योगिकी और उभरती प्रौद्योगिकियों के**

**लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।**

### प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्योग जगत की भागीदारी

- डीआरडीओ के विकास सह उत्पादन भागीदार ढांचे ने 134 भागीदार कंपनियों को प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की।
- 2,180 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
- मार्च 2026 तक उद्योग के उपयोग के लिए 2,780 से अधिक आईपीआर खोले गए।

### स्वदेशीकरण और घरेलू विनिर्माण

- मई 2026 तक, 10 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों, डीएमए और डीडीपी की पांच-पांच, 5,521 वस्तुओं को शामिल करते हुए अधिसूचित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ी।
- **सृजन डिफेंस इक्विपमेंट एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म (डीईपी) स्वदेशी रक्षा सोर्सिंग को बढ़ावा देने वाला एक डिजिटल रिपॉजिटरी है। मई 2026 तक, इसने 41,000 से अधिक विक्रेताओं और 2.7 लाख उत्पादों को सूचीबद्ध किया, जिससे घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत हुई।**
- अप्रैल 2026 तक, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने ₹42,057 करोड़ की निवेश प्रतिबद्धताओं को आकर्षित किया था, जिसमें ₹4,409 करोड़ खर्च किए गए।
- तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने ₹32,699 करोड़ को आकर्षित किया, जिसमें ₹6,446 करोड़ खर्च किए गए, जिससे भारत का रक्षा विनिर्माण आधार मजबूत हुआ।
- लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा ने मिसाइलों का निर्माण शुरू कर दिया है।

### कारोबारी सुगमता और रक्षा व्यापार

- औद्योगिक लाइसेंस की वैधता 7 (+3) वर्ष से बढ़ाकर 15 (+3, 18 वर्ष तक) वर्ष कर दी गई थी, जिसकी आजीवन वैधता अब शस्त्र अधिनियम के तहत दी गई है।
- नया डिफेंस एक्जिम पोर्टल शुरू से अंत तक आवेदन प्रक्रिया, स्वचालित कंपनी सत्यापन, सरलीकृत पंजीकरण, तत्क्षण ट्रैकिंग और सुरक्षित भुगतान एकीकरण को सक्षम बनाता है, जिससे रक्षा व्यापार स्पष्ट और अधिक कुशल हो जाता है।
- रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को स्वचालित मार्ग के तहत 74 प्रतिशत और सरकारी मार्ग के माध्यम से शत-प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था, जिससे मार्च 2026 तक 6,670.59 करोड़ रुपये का प्रवाह हुआ।

सुधारों ने मजबूत संस्थागत समर्थन और नवाचार से तैनाती तक स्पष्ट मार्गों के साथ रक्षा विनिर्माण के लिए अधिक सक्षम वातावरण बनाया है।

## भारत के रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता: वत्त वर्ष 2025-26

भारत के रक्षा परिदृश्य में अधिक घरेलू क्षमता, तकनीकी परिष्कार और परिचालन को लेकर अनुकूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। स्वदेशी विकास अब गोला-बारूद, मिसाइलों, प्रणोदन, वायु रक्षा और नौसैनिक प्लेटफार्मों तक फैला हुआ है, जो सरकार और उद्योग जगत के बीच मजबूत सहयोग द्वारा समर्थित है।

### स्वदेशीकरण परिचालन से आत्मनिर्भरता को मजबूती

- भारतीय सेना ने अपनी सूची में 175 गोला-बारूद वेरिएंट में से 159 को स्वदेशी बनाकर लगभग 91 प्रतिशत आत्मनिर्भरता हासिल की।
- भारत ने अग्नि-4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और अग्नि-5 लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो उनके परिचालन और तकनीकी मापदंडों को मान्य करता है।
- तारा ग्लाइड वेपन और रुद्रएम-II हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल ने भी जमीनी लक्ष्यों के खिलाफ स्वदेशी सटीक-स्ट्राइक क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
- डीआरडीओ ने कई स्वदेशी प्रणालियों को उन्नत किया है, जिसमें कुश लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल और बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली (वीएसएचओआरडीएस) शामिल हैं। मिसाइल इंटरसेप्टर, कम दूरी के हथियारों और लेजर प्रौद्योगिकियों के संयोजन वाली एक एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।
- डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में सहायता करते हुए सक्रिय रूप से कूल्ड स्क्रैमजेट कम्बस्टर का 12 मिनट का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया।

### समुद्री रक्षा और स्ट्राइक क्षमताओं का विस्तार

- भारतीय नौसेना ने आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरि और आईएनएस वाघशीर सहित 12 युद्धपोतों और पनडुब्बियों को कमीशन किया।
- **स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरि ने भी 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ सेवा में प्रवेश किया।**
- **अगली पीढ़ी के 11 अपतटीय गश्ती जहाजों में से पहला शची लॉन्च किया गया। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे को भी स्वदेशी संधायक-श्रेणी के सर्वेक्षण बेड़े को पूरा करने, समुद्री निगरानी और सर्वेक्षण क्षमताओं का विस्तार करने के लिए नौसेना में शामिल किया गया।**
- डीआरडीओ ने नौसेना एंटी-शिप मिसाइल-मीडियम रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया। यह विविध हवाई और समुद्री खतरों का मुकाबला करने की भारत की क्षमता को मजबूत कर रहा है।

भारत के रक्षा क्षेत्र के बदलाव से सैन्य तैयारियों, विनिर्माण और आंतरिक सुरक्षा में काफी मजबूती आई है।

## भारत के रक्षा क्षेत्र की महत्वाकांक्षा को 2047 तक मजबूती

भारत का रक्षा परिवर्तन अधिक आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और वैश्विक आत्मविश्वास की दिशा में एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है। मजबूत स्वदेशी उत्पादन, अनुसंधान और विकास, नवाचार और उद्योग की भागीदारी भूमि, वायु और समुद्री क्षेत्रों में रक्षा क्षमता को बढ़ा रही है। बढ़ते निर्यात और रणनीतिक साझेदारी एक विश्वसनीय वैश्विक रक्षा भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत कर रही है। उन्नत प्रौद्योगिकियों और घरेलू विनिर्माण में निरंतर निवेश के साथ, भारत भविष्य की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने और 2047 तक तकनीकी रूप से उन्नत रक्षा शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक क्षमताओं का निर्माण कर रहा है।

## संदर्भ:


**रक्षा मंत्रालय**

- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2273824&reg=48&lang=1
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2248124&reg=3&lang=1
- https://ddpdashboard.gov.in/
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2210154&reg=3&lang=1
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2213690&reg=48&lang=1&utm_source
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2292330&reg=48&lang=1

- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2295678&reg=48&lang=1
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2158574&reg=48&lang=1&utm_source
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2258934&reg=48&lang=1&utm_source
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2268099&reg=48&lang=1&utm_source
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2210154&reg=3&lang=1
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2247343&reg=48&lang=1
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2281806&reg=48&lang=1&utm_source
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2272374&reg=48&lang=1&utm_source
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2158574&reg=48&lang=1&utm_source
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2288526&reg=48&lang=1&utm_source
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2288576&reg=48&lang=1
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2233776&reg=48&lang=1
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2227772&reg=48&lang=1
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2264604&reg=48&lang=1
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2227775&lang=1&reg=3&utm_source

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

- https://newsonair.gov.in/government-sets-target-of-3-lakh-crore-rupees-defence-production-by-2029/

**पत्र सूचना कार्यालय**

- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2222601&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2273854&reg=3&lang=1
- https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=156103&lang=3&reg=3&utm_source
- https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=159313&lang=2&reg=48&utm_source
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2275082&reg=3&lang=1

**पीआईबी रिसर्च**

**पीके/केसी/एसकेएस/एम**